(अंग्रेजी परिपत्र का हिंदी अनुवाद)

आल इंडिया इन्सुरेंस एम्प्लोयीज एसोसिएशन

एलआईसी भवन सचिवालय रोड हैदराबाद **500 063**

(ईमेल: aiieahyd@gmail.com)

वृत्त. क्रमांक 16 / 2022	25 अप्रैल, 2022

प्रति,

सभी जोनल/मंडल/राज्य/क्षेत्रीय इकाइयां

प्रिय कॉमरेड,

हम एलआईसी आईपीओ और हमारे विरोध कार्रवाई के मुद्दे पर आज AIIEA और AILICEF द्वारा जारी एक संयुक्त परिपत्र के नीचे यहां पुन: पेश कर रहे हैं। कृपया कर्मचारियों के बीच इसका व्यापक प्रसार सुनिश्चित करें।

अभिवादन के साथ,

आपका साथी

Shreekant Mishra

महासचिव

आल इंडिया इन्सुरेंस एम्प्लोयीज एसोसिएशन
आल इंडिया एलआईसी एम्प्लोयीज फेडरेशन

दिनांक: 25.04.2022

प्रति,

सभी एलआईसी कर्मचारी

एलआईसी के आईपीओ का विरोध

सदस्यता खुलने के दिन दो घंटे की हड़ताल

सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम को शेयर बाजार में उतारना चाहती है और उसका आईपीओ ले आने के लिए तत्पर है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार निगम के बोर्ड ने 5 प्रतिशत के बजाय 3.5 प्रतिशत के आईपीओ को ले आने का फैसला किया है। एक अनुमान के अनुसार इससे सरकार को लगभग 21 हजार करोड़ रुपये हासिल होंगे। निगम इस बारे में अपना संशोधित प्रस्ताव सेबी के सामने जल्दी ही प्रस्तुत करेगा। इस प्रस्ताव से यह बात साफ दिखाई देती है कि अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकार किस तरह से बेचैन है। इस बेचैनी को ऐसे भी समझा जा सकता है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने एल आई सी के पहले वैल्यूएशन को 15 लाख करोड़ रुपये से घटाकर अब महज 6 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।

यह निगम के पॉलिसीधारको और आम जनता के साथ धोखा है, जिन्होंने निगम पर हमेशा भरोसा जताया है। यह औने पौने मूल्य पर एल आई सी की संपत्ति को बेचने की शर्मनाक कोशिश है, जिसे निगम के कर्मचारियों और पॉलिसीधारको ने अपने खून और पसीने से सींचा है। सरकार के प्रवक्ता खुलेआम कह रहे हैं कि शेयर मूल्य को कम रखा जाएगा जिससे कि निवेशकों को फायदा हो सके। नव-उदारवाद की यह योजना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नही है।

सरकार मई के पहले सप्ताह में एलआईसी का आईपीओ ले आना चाहती है। इस आईपीओ को ले आना जनभावनाओं के खिलाफ तो है ही, इसको ले आने का समय और भी बुरा है। भारत का शेयर बाजार इस समय बहुत अस्थिर है। खासकर रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद विदेशी निवेशकों ने इस वर्ष भारत से लगभग 16 बिलियन डॉलर निकाल लिए हैं। भारत ने अपने विकास का लक्ष्य 1.8 प्रतिशत खो दिया है । महंगाई दर ने केंद्रीय बैंक के अनुमान को पहले ही पीछे

छोड़ दिया है। और सरकार के कुप्रबंधन के कारण रुपये की कीमत लगातार गिरती जा रही है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन सबके बावजूद सरकार एलआईसी के आईपीओ को ले आने के लिए आमादा है। बीमा कर्मचारियों ने गत 28 वर्षों से भारतीय जीवन बीमा के निजीकरण को सफलतापूर्वक रोक रखा है। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट के समय से ही बीमाकर्मियों ने जनता के सहयोग से यह संघर्ष लड़ा है और निगम को नुकसान पहुंचाने वाली सरकारों की तमाम नीतियों को लागू नहीं होने दिया है।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह आईपीओ निगम के निजीकरण की दिशा में उठाया गया पहला कदम है । नवउदारवादी नीतियों से समझौता कर चुकी सरकार सिर्फ 3.5 प्रतिशत के विनिवेश पर नही रुकेगी। बैंक और सामान्य बीमा के उदाहरणों से यह समझा जा सकता है कि वे भारतीय जीवन बीमा निगम के निजीकरण के लिए भी जरूर ही प्रयास करेंगे। इसलिए हमें जन सहयोग से इसका मुकम्मल विरोध करना ही पड़ेगा। हम निगम के कर्मचारी इसके विरोध में गत 28 और 29 मार्च को दो दिवसीय हड़ताल कर चुके हैं, जिसमें अन्य श्रमिक वर्गों ने भी भाग लिया था। इस संघर्ष को हमे और आगे बढ़ाना है।

निगम में विनिवेश की शुरुआत ने विधिक और नैतिक सवाल खड़े किए हैं । निगम का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था कि जनता के पैसे को सुरक्षित रखा जाय और सार्थक दिशा में उपयोग किया जाय। सरकार इसकी ट्रस्टी बनी थी। 1956 के प्रावधानों के अनुसार सरकार ने निगम को 5 करोड़ रुपये का शुरुआती धन उपलब्ध कराया था और कहा था कि निगम जब भी महसूस करे उसे कम किया जा सकता है। और निगम से कहा गया था कि वह उन कंपनियों को मुआवजा दे, जिनको उसने टेकओवर किया है। निगम ने सरकार द्वारा दिये गए पैसे से अधिक इस मुआवजे के मद में भुगतान किया। इससे स्पष्ट होता है कि निगम का सारा व्यवसाय पॉलिसीधारको के पैसे से संभव

हुआ है, इसलिए उनका ही इस पर अधिकार भी है। सरकार इस सम्पत्ति को कुछ चुनिंदा लोगों को सौंपना चाहती है, जो सिरे से अनैतिक है।

इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि हम सरकार की इन गलत नीतियों का पुरजोर विरोध करें। इसलिए हम सभी बीमाकर्मियों से आह्वान करते हैं कि जिस दिन आईपीओ को ओपन किया जाय, उस दिन भोजनावकाश से पहले 2 घंटे की बहिर्गमन हड़ताल करें। इसमें शामिल होने के लिए हमने संस्थान के अन्य श्रमिक संगठनों को भी पत्र लिखा है। हम उम्मीद करते हैं कि वे सभी भी इस हड़ताल में शामिल होंगे और निगम, बीमाकर्मियों तथा देश को सुरक्षित रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ,

आपका साथी

श्रीकांत मिश्रा

महासचिव, ए आई आई ई ए